

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :  
: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :  
: आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015. :

क फाइल संख्या : File No : V2(84)53 /Ahd-III/2015-16/Appeal-I

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-018-16-17

दिनांक Date : 25.05.2016 जारी करने की तारीख Date of Issue 25/5/16

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-I) Ahmedabad

ग \_\_\_\_\_ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल  
आदेश सं \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: 21/CE/REF/DC/2015-16-Refund Date: 24.07.2015  
Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kalol, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Lubi Industries LLP

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे  
बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as  
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

**Revision application to Government of India :**

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में  
पूवोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार,  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को  
की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision  
Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building,  
Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the  
following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने  
में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में  
चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

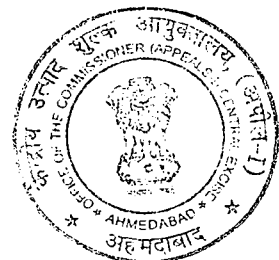
(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a  
warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of  
processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क  
कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित  
है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside  
India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any  
country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया  
माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of  
duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- षोबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

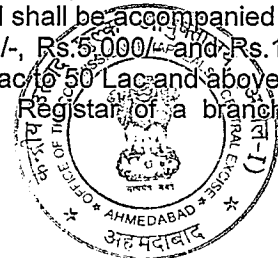
(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1988 की धारा 39F के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



**ORDER-IN-APPEAL**

This appeal has been filed by M/s **Lubi Industries LLP, A1 & A2, Lubi Industrial Park, Vadsar, Taluka Kalol, District Gandhinagar** (hereinafter referred to as "the appellant") against Order-in-Original No.21/CE/Ref/2015-16-Refund dated 27.07.2015 (hereinafter referred to as "the impugned order" passed by the Deputy Commissioner of Central Excise, Kalol Division, Ahmedabad-III (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Briefly stated, the facts of the case is that the appellant had filed a rebate claim of Rs.2,73,249/- before the jurisdictional officer on 02.05.2014 for the duty paid on goods exported vide ARE-1 No.09/2013-14 dated 14.04.2014. Since the appellant had not submitted the copies of ARE-1 (in original, duplicate and triplicate) along with the said claim, which is required for verification of the details of exported goods and also prescribed under Notification 19/2004 CE (NT) dated 06.09.2004, the said claim was rejected by the jurisdictional Deputy Commissioner vide order dated 13.10.2014. Being aggrieved, the appellant filed an appeal before Commissioner (Appeals) who allowed the said appeal vide order dated 13.01.2015, by way of remand with consequential relief. The adjudicating authority again rejected the refund claim, vide the impugned order on the same ground that the appellant have failed to submit the vital document viz ARE-1 original, duplicate and triplicate copies and in absence of the said documents refund cannot be sanctioned as per Notification 19/2004-CE (NT).

3. Being aggrieved, the appellant has filed the present appeal on the grounds that there is a grave jurisdiction error on the part of the adjudicating authority in rejecting the rebate claim in as much as he has no jurisdiction to bypass the directions of Commissioner (Appeals); that the Commissioner (Appeals) has specifically held that a Bond or an undertaking could be obtained from the appellant for the alleged misplaced/lost ARE-1s, yet the adjudicating authority has rejected the claim without following the said direction. The Commissioner (Appeals) has set aside the order dated 13.10.2014 and allowed the case by remand back with consequential relief. However, the adjudicating authority has rejected the claim on the same grounds as narrated in the order dated 13.10.2014. By number of decisions rendered by the appellate authority as well as the Govt. of India, it is decided that a benefit given by the Government for enhancing exports could not be denied for any technical reasons or venial infractions.

4. A personal hearing in the matter was held on 03.05.2016 and Shri C.R Pillai, Export Manager appeared for the same. He reiterated the grounds of appeal and stated that the department has filed an appeal against Order-in-Appeal dated 13.01.2015.

4.1 I have carefully gone through the facts of the case, submissions made in the appeal and at the time of personal hearing. The limited point to be decided



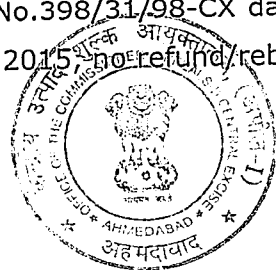
in the matter is whether the appellant is eligible for the rebate of exported goods in case of loss of ARE-1 original, duplicate and triplicate copies.

4.2 I find that the eligibility of rebate claim in absence of original, duplicate copy of ARE-1 has been decided by the appellate authority in various cases on the basis of authoritative pronouncement of Hon'ble High Court/Tribunal. I further find that the Commissioner (Appeals) vide OIA dated 13.01.2015 has also decided the instant issue by following the decisions of Hon'ble High Court of Bombay in the case of M/s UM Cables Ltd reported in 2013 (293) ELT 641 (Bom). The Commissioner (Appeals), in his OIA dated 13.01.2015, by remanding back the case to the adjudicating authority has held that non production of copies of ARE-1 cannot be invalidate rebate claim and the exporter can demonstrate by cogent evidence to the effect that the goods were exported on payment of duty. The logic behind the case remanded to the adjudicating authority vide the said OIA dated 13.01.2015 was to verify the supporting documents related to export of goods submitted by the appellant in absence of ARE-1. On perusal of the impugned order, I find that the adjudicating has not gone through the OIA dated 13.01.2015 properly and mis-interrupted the case law relied on.

4.3 I find that there are also other authoritative decisions in the matter that non production of original, duplicate, triplicate copy of ARE-1 cannot invalidate rebate claim. The Government of India, in their revision order dated 12.10.2010 in the case of M/s Gard Tax-o-Fab Pvt Ltd has held that Instead of rejecting the rebate claims for non-submission of original documents, the original authority should have considered collateral evidence to verify whether duty paid goods have actually been exported or not as per provisions of C.B.E. & C.'s Central Excise Manual of Supplementary Instructions. Further, in the case of M/s Zandu Chemicals Ltd. reported in 2015 (315) ELT 520 (Bom), the Hon'ble High Court of Bombay held that Rebate claim could not be rejected for their non-submission of original ARE-1s, as there was proof of export of goods in other documents like shipping bill on which ARE1 was mentioned; that condition of submission of original as well as duplicate copies of ARE1 was only directory/procedural, and not mandatory.

4.4 In view of above discussed authoritative pronouncements, I am of the opinion that the order passed by the adjudicating is unsustainable and it is manifestly erroneous.

4.5 I further find that the adjudicating authority, in the impugned order, has stated that the department has filed an appeal before the Revisionary Authority, New Delhi, challenging the Order-in-Appeal dated 13.01.2015 and one of the ground of appeal is regarding the essential condition for sanction of claim for rebate prescribed in Notification No.19/2004 CE (NT) dated 06.09.2004. It is pertinent to point out here that as per Board's Circular No.398/31/98-CX dated 02.06.1998 and F No.276/186/2015-CX 8 A dated 01.06.2015, no refund/rebate



claim should be with held on the ground that an appeal has been filed against the order giving the relief (order of Commissioner (Appeals)/Commissioner of Central Excise & Customs/CESTAT), unless stay order has been obtained. Further, as per Board's circular No.432/56/98-CX dated 22.09.1988, the departmental authority can issue protective demand under relevant provisions of the Central Excise Act, 1944 for recovery of such refund sanctioned. In the circumstances, I do not find any merit in the impugned order for rejecting the rebate claim by not following Commissioner (Appeals) order dated 13.01.2015 and supporting case laws.

4.6 In view of above discussion and following the ratio of decisions as mentioned at para 4.3 and also following the ratio of M/s UM Cables Ltd case, I set aside the impugned order and remand back the case to the adjudicating authority for considering the rebate claim in above terms.

5. The appeal is disposed off in above terms.

*Uma Shanker*

(UMA SHANKER)  
COMMISSIONER (APPEALS-I)  
CENTRAL EXCISE,  
AHMEDABAD

25/05/2016

Attested

*Mohan V.V.*  
(Mohan V.V)  
Superintendent (Appeals-I)  
Central Excise, Ahmedabad

By R.P.A.D.

To  
M/s Lubi Industries LLP, A1 & A2,  
Lubi Industrial Park, Vadsar, Taluka Kalol,  
District Gandhinagar  
Copy to:-



1. The Chief Commissioner, Central Excise Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III
3. The Addl./Joint Commissioner, (Systems), Central Excise, Ahmedabad-III
4. The Dy. / Asstt. Commissioner, Central Excise, Division- Kalol, Ahmedabad-III
5. Guard file.
6. P.A (Commissioner-Appeals-I) file.